

भारत-न्यूजीलैंड के बीच एफटीए पर मुहर, पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन से फोन पर की बात

(एजेंसी) नयी दिल्ली। न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बेहद गहरा करेगा, बाजार पहुंच को व्यापक करेगा और निवेश प्रवाह को बढ़ावा देगा। भारत ने सोमवार को बयान में यह बात कही। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन ने दोनों देशों के बीच एक "ऐतिहासिक" मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत संपन्न होने की सोमवार को घोषणा की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने फोन पर बातचीत की जिसके बाद मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर वार्ता संपन्न होने की घोषणा की गई। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा, " दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी एवं



संयुक्त रूप से घोषणा की।" इसमें कहा गया है कि दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जाहिर की कि नौ महीने के रिकॉर्ड समय में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का संपन्न होना दोनों देशों के बीच

संबंधों को और गहरा करने की साझा महत्वाकांक्षा एवं राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है। विदेश मंत्रालय ने कहा, " यह मुक्त व्यापार समझौता, द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव को गहरा करेगा, बाजार पहुंच को व्यापक बनाएगा, निवेश प्रवाह को बढ़ावा देगा तथा दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग

को मजबूत करेगा। साथ ही यह, दोनों देशों के नवोन्मेषकों, उद्यमियों, किसानों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, छात्रों तथा युवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगा।" इसमें कहा गया है कि दोनों नेताओं ने अगले पांच वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के साथ-साथ अगले 15 वर्ष में न्यूजीलैंड के भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने को लेकर विश्वास व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, " दोनों नेताओं ने खेल, शिक्षा एवं लोगों के बीच संबंधों जैसे द्विपक्षीय सहयोग के अन्य क्षेत्रों में हासिल की गई प्रगति का भी स्वागत किया। साथ ही भारत-न्यूजीलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।"

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने सब कुछ बदल दिया : आनंदीबेन

- देश से घुसपैठियों को एसआईआर के जरिए निकालने का हो रहा काम
- एसवीएम के बालिका इंटर कालेज भवन का राज्यपाल ने किया शुभारंभ

न्यूज वाणी ब्यूरो फतेहपुर। विद्याभारती से संचालित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज परिसर में सरस्वती

कॉलेज के भवन का शुभारंभ करने आई सूबे की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि गांव और शहर के गरीब बच्चों

केंद्रों में जनसहयोग से काफी काम हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं लाभार्थियों तक नहीं

होगा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल राज्यपाल ने कहा कि सरकार की शुरु की गई घरौनी योजना के तहत लोगों को उनके आवास की पहचान मिलेगी। पहले की सरकारों ने घरौनी के लिए कुछ भी नहीं किया है, जिससे लोगों के घरों की कोई पहचान नहीं थी। उन्होंने महिला उत्पीड़न पर सवाल उठाते हुए कहा कि दहेज की बीमारी को समाज से शिक्षा के जरिए खत्म किया जा सकता है। इसलिए बालिकाओं का शिक्षित होना नितांत आवश्यक है। क्योंकि यही बालिकाएं ही देश के भविष्य की जननी होंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किशोर बच्चियों के व्यवहार पर नजर रखने की जरूरत है।



विद्या मंदिर बालिका इण्टर के लिए संचालित आंगनबाड़ी पहुंची है उसके लिए काम करना

पश्चिम बंगाल: ममता बनर्जी ने एसआईआर से पहले बूय-स्तरीय सहायकों के लिए कार्यसूची की तैयार

(एजेंसी) कोलकाता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे चरण के दौरान पार्टी के बूय-स्तरीय सहायकों (बीएलए) को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में सोमवार को विस्तृत निर्देश जारी किये। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक जन सभा को संबोधित करते हुए बनर्जी ने चरणबद्ध कार्यसूची की रूपरेखा प्रस्तुत की और सतर्कता, पारदर्शिता और जमीनी स्तर पर भागीदारी पर जोर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से बाहर न रह जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मूल, स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाताओं की सूचियां आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रकाशित की जाएंगी और साथ ही जिला, उपमंडल, ब्लॉक और नगरपालिका कार्यालयों में भी प्रदर्शित की जाएंगी। बीएलए को इन सूचियों के आधार पर घर-घर जाकर सत्यापन करने का निर्देश दिया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि हटाए गए या अनुपस्थित के रूप में दिखाये गये कोई भी मतदाता वास्तव में दिए गए पते पर रह रहे हैं या नहीं। यदि ऐसे मतदाता पाए जाते हैं, तो बीएलए को उन्हें पुनः नामांकन के लिए फॉर्म 6 और अनुलग्नक 4 को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को जमा करने में सहायता करनी

चाहिए। बनर्जी ने बूय स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा ध्मानात्मक के रूप में चिह्नित मतदाताओं की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि बीएलए को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे सभी मतदाताओं को नोटिस मिल गए हों और वे 2002 की मतदाता सूची की प्रति और चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेजों में से किसी एक के साथ सुनवाई के लिए तैयार हों। जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें उन्होंने स्थायी निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी, जैसा भी लागू हो) के लिए तत्काल आवेदन करने की सलाह दी। प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) कार्यालयों में सरकारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। बीएलए को बीएलओ ऐप में तार्किक विसंगतियों के रूप में चिह्नित



इस बात पर जोर दिया कि मतदाताओं को सुनवाई के दौरान अनावश्यक उत्पीड़न का सामना नहीं करना चाहिए और उनकी सहायता के लिए बूय स्तरीय शिविरों का आह्वान किया। उन्होंने कि गायकों ब्लॉक अध्यक्षों और पार्षदों को जिम्मेदारी सौंपी और चेतावनी दी कि यदि आवश्यक हुआ तो कार्यक्षीन पार्टी

नेताओं को बदल दिया जाएगा। उन्होंने कहा, कई पार्षद काम नहीं करते और पार्टी की बदनामी ही करते हैं। जरूरत पड़ने पर मैं नए ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त करूंगी। जो अच्छा काम करेंगे, उन्हें

जिम्मेदारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बीएलए को फॉर्म 6 और फॉर्म 8 के माध्यम से जमा किए गए आवेदनों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। आवेदकों की सहायता करते समय, फॉर्म 6 जमा करने वाले 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की विशेष रूप से जांच करने की सलाह दी गई।

सुरक्षा बलों ने कश्मीर में बरखी स्टेडियम के आसपास के इलाकों में चलाया तलाशी अभियान

(एजेंसी) श्रीनगर। सुरक्षा बलों ने यहां बरखी स्टेडियम के आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बरखी स्टेडियम कश्मीर में गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आयोजन स्थल है। अमीराकदल और महाराजा बाजार के घनी आबादी वाले व्यावसायिक क्षेत्रों की कुछ आवासीय इकाइयों में विस्फोटक, हथियार और गोला-बारूद की तलाश के लिए खोजी कुतों और मेटल डिटेक्टर की मदद ली गई। अधिकारियों ने बताया कि अब तक सुरक्षा बलों को तलाशी के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि तोड़फोड़ विरोधी जांच और तलाशी अभियान बरखी स्टेडियम के निकट स्थित क्षेत्रों में चलाए गए जो कश्मीर में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य स्थल है। लाल चौक स्थित ऐतिहासिक ब्लॉक टावर अमीराकदल से कुछ ही दूरी पर स्थित है जहां तलाशी अभियान चलाया गया। ब्लॉक टावर पिछले चार वर्षों में एक पर्यटन केंद्र में बदल गया है।

सीएम योगी ने सदन में वदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत

कहा- वदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम की चेतना का उद्घोष

(एजेंसी) लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को वि

कहा कि वंदेमातरम स्वतंत्रता संग्राम की चेतना का उद्घोष है। मुख्यमंत्री ने कहा कि



ानसभा में राष्ट्रगीत वंदेमातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर चर्चा की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने

वंदेमातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा और क्रांतिकारियों की सच्ची भावना का प्रतीक है।

उन्होंने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश की राजधानी दिल्ली से शुरू हुई कार्यक्रमों की शृंखला के तहत उत्तर प्रदेश विधानसभा संभवतः पहली ऐसी विधानसभा है, जहां राष्ट्रगीत वंदेमातरम पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। इसके लिए उन्होंने पूरे सदन का हृदय से स्वागत और आभार व्यक्त किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा जब हम वंदेमातरम का स्मरण करते हैं, तो यह हमें आजादी के आंदोलन की चेतना, त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। यह गीत देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रप्रेम का उद्घोष करता है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान

देशवासियों को एक सूत्र में बांधाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि वंदेमातरम आज भी हर भारतीय के मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण और कर्तव्यबोध की भावना को जागृत करता है। गौरतलब है कि इससे पहले सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 24,496.98 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया। संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में बजट पेश करते हुए बताया कि वर्ष 2025-26 का मूल बजट 8 लाख 8 हजार करोड़ रुपये का था, जिसके सापेक्ष अनुपूरक बजट का आकार 3.03 प्रतिशत है।

वन भूमि अतिक्रमण पर पर बोली सुप्रीम कोर्ट-मूक दर्शक की तरह बैठी है उत्तराखंड सरकार

(एजेंसी) नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले में सोमवार को उत्तराखंड सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि राज्य सरकार और उसके अधिकारी "मूक दर्शक" की तरह बैठे रहे और अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की अवकाशकालीन पीठ ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को एक जांच समिति गठित करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, "हमारे लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उत्तराखंड सरकार और अधिकारी अपनी आंखों के सामने वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को मूक दर्शक की तरह देख रहे हैं। इसलिए हम इस मामले पर स्वतः संज्ञान ले

रहे हैं।" न्यायालय ने कहा, "उत्तराखंड के मुख्य सचिव और प्रधान संरक्षण सचिव को एक



तथ्य अन्वेषण समिति गठित करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। निजी पक्षों को किसी भी प्रकार का तीसरा पक्ष बनाने से रोका जाता है और कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा।" उच्चतम न्यायालय

ने कहा कि आवासीय मकानों को छोड़कर खाली पड़ी जमीनों पर वन विभाग का कब्जा होगा।

आरक्षण नीति विवाद: उमर अब्दुल्ला ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से की मुलाकात, दिए कई आश्वासन

(एजेंसी) श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आवास के बाहर आरक्षण नीति के खिलाफ सोमवार को सांसद और नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेका) के नेता रूहुल्लाह मेहदी के नेतृत्व में कई राजनीतिक नेताओं और बड़ी संख्या में छात्रों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जिसे इस साल की शुरुआत में उपराज्यपाल-प्रशासन ने द्वारा पेश किया गया था। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा श्आज मैंने ओपन मेरिट स्टूडेंट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। लोकतंत्र की खूबसूरती आपसी सहयोग की भावना से सुनने और बातचीत करने का अधिकार है। अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने उनसे कुछ अनुरोध किए हैं और उन्हें कई आश्वासन दिए हैं। उन्होंने कहा, श्आज का यह चौनल बिना किसी बिचौलिए या पिछलग्गू के खुला रहेगा। उमर अब्दुल्ला सरकार ने 10 दिसंबर को नौकरियों और प्रवेश में आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च

न्यायालय आरक्षण नीति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसने हाल ही में सरकार से इस पर जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री से



मुलाकात के बाद एक छात्र प्रतिनिधि ने कहा कि 30 मिनट लंबी बैठक का मुख्य निष्कर्ष यह था कि मुख्यमंत्री ने उप-समिति को अपना काम पूरा करने के लिए छह महीने का समय मांगा है। इससे पहले आरक्षण के मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के रूहुल्लाह, वहीद पारा और इल्लिजा मुफ्ती और अवामी इतिहाद पार्टी के नेता शेख खुशींद- सांसद इंजीनियर राशिद के भाई जैसे राजनीतिक

विरोधी एक साथ आए थे। प्रदर्शनकारियों ने श्ओपन मेरिट उम्मीदवारों के लिए न्याय्, श्योग्यता के लिए प्रयास करें, महानता प्राप्त करें के नारे लिखी

होना चाहते थे। हालांकि उनकी घोषणा के पांच मिनट के भीतर ही उन्हें कथित तौर पर उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया। मीरवाइज ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा आरक्षण के मुद्दे को जिम्मेदार लोगों द्वारा न्याय और निष्पक्षता के साथ संबोधित किया जाना चाहिए, समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करनी चाहिए न कि किसी एक समूह की कीमत पर। आरक्षण की वर्तमान स्थिति सामान्य,ओपन मेरिट श्रेणी के हितों को कम करके ऐसा करती है। उनकी चिंताओं को तुरंत दूर करने की हार्दिक अपील! ओपनमेरिटस्टूडेंट्सएसोसिएशन का समर्थन करें। उल्लेखनीय है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने पहाड़ी समुदाय के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया। इस बदलाव ने विभिन्न श्रेणियों में कुल आरक्षित सीटों को 60 प्रतिशततक बढ़ा दिया जिससे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए केवल 40 प्रतिशत सीटें ही उपलब्ध रहें। इसने ओपन मेरिट के उम्मीदवारों के बीच अशांति पैदा कर दी, जो नई नीति की समीक्षा की मांग कर रहे हैं।

सम्पादकीय आरक्षण देने में भूल हुई या बेईमानी

देश में आरक्षण व्यवस्था सामाजिक न्याय की रीढ़ मानी जाती है, लेकिन जब उसी व्यवस्था के साथ योजनाबद्ध छेड़छाड़ होने लगे, तो यह लोकतंत्र और संविधान दोनों के लिए गंभीर खतरा बन जाती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती के घ्यारी विज्ञापन में जो हुआ, उसने यह साबित कर दिया कि अब आरक्षण की बेईमानी ही नहीं बल्कि खुलेआम डकैती की जा रही है। इसके पीछे इंडब्ल्यूएस है?। शायद यही कारण था मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूूूू ललित ने इंडब्ल्यूएस आरक्षण पर असहमति जताई थी। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के विज्ञापन में कुल 7994 पद के सापेक्ष ओबीसी वर्ग को मिलने वाली 27 प्रतिशत आरक्षित सीटों के अनुसार लगभग 2158 पद होते हैं लेकिन

नफीस जाफरी

ओबीसी को 1441 पद ही दिए गये। इंडब्ल्यूएस को अलग से पद देने की जगह ओबीसी की सीटों से दे दिया गया। ओबीसी की चोरी की गई 717 पदों को इंडब्ल्यूएस के रूप में दिया गया। यह बेईमानी किसी को समझ में न आए इसके लिए इंडब्ल्यूएस को 792 पद दिया गया। विचार करने वाली बात यह है कि लगभग जितनी सीट इंडब्ल्यूएस की है उसी के लगभग ओबीसी की सीटों की बेईमानी हुई है। इसकी गणितीय गणना में इंडब्ल्यूएस को मिलने वाली 792 सीटों में से ओबीसी की बेईमानी की गई 717 सीटों को घटाया जाए तो 75 सीट ही ज्यादा है। यह इसलिए भी किया गया ताकि गणितीय गुणा गणित में सीटों का अंतर पाया जाय । ताकि यह साबित हो सके कि ओबीसी पदों की बेईमानी नहीं की गई और न ही इंडब्ल्यूएस को ओबीसी कोटे को घटाकर दिए जाने की कोई संसा थी। यह कोई प्रशासनिक भूल नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। उद्देश्य साफ था। ओबीसी समाज के हक को छीनकर उसे ऐसे वर्ग को देना। लेकिन इस बार बेईमानी भर्ती से पहले पकड़ी गई। सिस्टम ने यह मान लिया था कि आंकड़ों की जटिलता में यह खेल दब जाएगा, लेकिन जागरूक युवाओं और सामाजिक संगठनों ने सच्चाई उजागर कर दी। सवाल यह है कि जब संविधान स्पष्ट रूप से सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की बात करता है, तो फिर आर्थिक आधार पर बनाया गया इंडब्ल्यूएस कोटा ओबीसी के हिस्से को क्यों खा रहा है? पिछड़ों दलितों का भला करने का दावा करने वाले लोगों पिछड़े दलितों को इंडब्ल्यूएस के दायरे से बाहर क्यों रखा गया और जब इंडब्ल्यूएस के नाम पर अलग से जनरल वर्ग को आरक्षण दे दिया तो चोरी की जरूरत क्यों पड़ गई। आज स्थिति यह है कि इंडब्ल्यूएस के माध्यम से पूरे सामाजिक न्याय के दांचे को कमजोर किया जा रहा है। यह आरक्षण की आत्मा पर हमला है। अगर आज ओबीसी की 700 से अधिक सीटें चुपचाप काटी जा सकती हैं, तो काल और भी अंधि कारार छीने जा सकते हैं। शायद यह सब कारण था की देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूूूू ललित और जस्टिस रविंद्र भट ने इंडब्ल्यूएस आरक्षण पर असहमति जताई थी। यूूूू ललित ने जस्टिस रविंद्र भट के राय से सहमति जताई थी कि एससी–एसटी और ओबीसी को इससे बाहर करना इस वर्ग के गरीब लोगों से भेदभाव होगा। जस्टिस एस रविंद्र भट ने इंडब्ल्यूएस आरक्षण पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा था जहां तक सामाजिक न्याय की बात है तो इसमें एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को भी शामिल किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आरक्षण के लिमिट को पार करना बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट ने अपना अल्पमत का विचार व्यक्त करते हुए इंडब्ल्यूएस आरक्षण संकंी संविधान संशोधन पर असहमति जताई और उसे रद्द कर दिया। प्रधान न्यायाधीश ललित ने न्यायमूर्ति भट के विचार से सहमति व्यक्त की थी। यदि इंडब्ल्यूएस में यूपीएससी वर्ग को शामिल करके आरक्षण दिया गया होता तो इस तरह की बेईमानी न होती और न ही सामाजिक द्वंद पैदा होता। लेखपाल भर्ती के विज्ञापन में हुई बेईमानी का पर्दाफाश होते ही एक बार पुनः उत्तर प्रदेश की व्यापम घोटाला कहा जाने वाला 69000 भर्ती चर्चा का विषय बन गया। यह प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जिसकी सुनवाई आगामी चार फरवरी को होनी है। 2018 में इस भर्ती के लिए विज्ञापन आया था भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है परीक्षा के कुछ सवालों पर भी आपत्ति अभ्यर्थी द्वारा की जाती है। हालांकि उतना विवाद नहीं होता जितना की परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद बनाई गई चयन सूची पर होता है। चयन सूची में विसंगति होने के संदेह पर आरक्षित वर्ग (पिछड़ा, दलित) के अभ्यर्थियों ने पुख्ता जानकारी जुटाया और सरकार से निवेदन किया की विसंगतियों को दूर कर उन्हें नौकरी दी जाए। सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इस मामले को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में ले गये। जांच पड़ताल के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया और उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया। रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू किया। अभ्यर्थियों का आंदोलन पूरे प्रदेशभर में चर्चा का विषय बन गया। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस बात को स्वीकार किया की ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने नौकरी देने का वादा किया और कुछ दिन बाद एक 6800 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी करवाई। अपनी नौकरी को लेकर कुछ अभ्यर्थी पहले ही हाई कोर्ट पहुंच चुके थे, जब यह लिस्ट आई तो यह लिस्ट भी कोर्ट पहुंच गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ लखनऊ की सिंगल बेंच का 13 मार्च 2023 को आदेश आता है। सिंगल बेंच के आदेश में दो महत्वपूर्ण बातें देखने को मिलती हैं पहला 6800 की सूची को कोर्ट रद्द कर देती है और दूसरा नए सिरे से 69000 भर्ती की लिस्ट रिव्यू करने का आदेश पारित करती है। 6800 की लिस्ट रद्द होने से उसमें शामिल अभ्यर्थी नाराज थे उन अभ्यर्थियों ने इस मामले को डबल बेंच में चैलेंज किया। डबल बेंच ने 13 अगस्त 2024 को पूरी 69000 भर्ती की चयन सूची को नए सिरे से बनाए जाने और आरक्षण नियमों का पालन किए जाने का आदेश पारित किया। ऐसे में कुछ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने महसूस किया कि यदि सूची नई बनाई जाएगी तो उनकी नौकरी जा सकती है क्योंकि हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सेवा नियम, 1981 के नियम 14 में बताए गए गुणवत्ता अंकों के संदर्भ में चयन सूची तैयार करने के बाद, आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 3 (6) के तहत सूची बनाने को कहा था, जिसे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अपनी जीत मान रहे। फिलहाल यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और यह पूरा प्रकरण आरक्षण से ही जुड़ा है।



गुलफिशा खान

पर्यावरण संरक्षण का मोदी सरकार का वादा उसके बाकी वादों की तरह न केवल खोखला है, बल्कि डरावना भी है। इस संरक्षण के नाम पर सरकार ने एक उद्योगपति को निजी जंगल बनाकर उसमें तमाम तरह के जानवर पालने की अनुमति दे दी। पूरी दुनिया में ऐसे भ्रष्टाचार की मिसाल नहीं मिलेगी। लेकिन पर्यावरण को लेकर सरकार के खौफनाक रवैये का यह अकेला उदाहरण नहीं है। नया उदाहरण 2 अरब साल पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला को सुप्रीम कोर्ट के जरिए मृत्युदंड सुनाने का है। सरकार की बनाई कमेटी की तय परिभाषा के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में खनन की जा अनुमति दी है, वह किसी मृत्युदंड से कम नहीं है। अ ग ड ` - पि छ ड ` , लोकतांत्रिक–तानाशाही वाले

सभी का सम्मान करें, लेकिन हर व्यक्तिहर चीज पर सदेह भी रखें



शनिवार शाम करीब 5.45 बजे मैं अनाउंसमेंट के इंतजार में जयपुर एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर कोने की सीट पर बैठा था। मेरी

छठी इंद्री ने कहा कि मेरे कंधे के ऊपर से कोई मुझे मोबाइल पर टाइप करते देख रहा है। जैसे ही उस अनजान व्यक्ति को देखने मैं पीछे मुड़ने का सोचा कि मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आयाटू सेंड ‘मी द ग्ग्ग्ग’। यह मेरे और पत्नी के बीच का कोड वर्ड है, हम कभी भी पासवर्ड नहीं कहते। पासवर्ड ढूँढ़ने के लिए मैसेज आइकन दबाने की बजाय मैंने स्क्रीन के दाहिनी ओर मौजूद कैमरा बटन और साथ ही रिवर्स कैमरा आइकन भी दबा दिया। कैमरा तुरंत मेरे और कंधे के पीछे मौजूद उस चेहरे पर फोकस हो गया। इससे पहले कि मैं उस चेहरे का स्क्रीनशॉट ले पाता, उस अनजान व्यक्ति का भारी बैकपैक मेरे कंधे से

भारत की सबसे बड़ी समस्या वायु प्रदूषण

अजीत द्विवेदी राजधानी दिल्ली और राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का हर शहर वायु प्रदूषण की आपदा का शिकार है। यह अलग बात है कि सरकार इसे आपदा स्वीकार करने को तैयार नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री त्रातापराव जाधव ने राज्यसभा में बताया कि ऐसा कोई आंकड़ा देश में उपलब्ध नहीं है, जो किसी बीमारी या मृत्यु को सीधे तौर पर वायु प्रदूषण से जोड़ सके। उन्होंने यह भी कहा कि लोगोंको सांस से संबंधित जो बीमारियां हो रही हैं उनमें हो सकता है कि एक कारण वायु प्रदूषण हो। इस तरह सरकार ने पल्ला झाड़ लिया और यह भी कह दिया कि सिर्फ वायु प्रदूषण से कोई बीमारी हो रही है या किसी की मौत हो रही है, इसका न कोई प्रमाण है और न कोई आंकड़ा है। दूसरी ओर लोकलसर्कल्स की ओर से कराए गए ताजा संक्षेपण में दिल्ली में 82 फीसदी लोगों ने माना है कि है उनके किसी न किसी परिचित या रिश्तेदार को वायु प्रदूषण के कारण सांस से जुड़ी बीमारी हुई है। आठ फीसदी लोग दिल्ली छोड़ कर जाने को तैयार हैं और 74 फीसदी लोग इलाज के खर्च को लेकर चिंता में हैं। यह सर्वे त्त का है, जब पड़ोस के राज्यों में किसानों का पराली जलाना बंद हो चुका है और फिर भी एक्यूआई सरकारी रीडिंग की अधिकतम सीमा पांच सौ तक पहुंचा हुआ है! असल में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई का लगातार श्वराबघ या श्वेहद खराबघ या शंभीरघ्य और श्वतरनराकघ श्रेणी में होना सिर्फ दिल्ली और एनसीआर की परिघटना नहीं है। धीरे धीरे यह पूरे देश की परिघटना बन गई है। देश के बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक हवा की खराब गुणवत्ता करोड़ों लोगों के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही है। गंगा

तमाम देशों में पर्यावरण के मुद्दों पर व्यापक बहस होती है, फिर भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाते हैं। लेकिन भारत शायद इकलौता देश है जहां सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर केंद्र की सिफारिश पर अपनी मुहर लगा दी और इसमें पर्यावरणविदों की राय जरूरी नहीं समझी गई। सरकार ने किसी पर्यावरणविद को भले सलाहकार नहीं बनाया, फिर भी अरावली में खनन के खिलाफ जो आवाजें चारों तरफ से उठ रही हैं, उन पर ही सर्वोच्च न्यायाल को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर क्या गलत हो रहा है, जिस पर इतना विरोध। हो रहा है।गौरतलब है कि अरावली पहाड़ियों की परिभाषा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पर्यावरण मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण, राज्यों के वन विभागों और सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई जिसे अरावली को परिभाषित करने को कहा गया। कमेटी ने कोर्ट के सामने अपनी अनुशंसा में कहा कि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात इन चार राज्यों में लगभग 670 किमी तक फैली अरावली पहाड़ियों में

वही पहाड़ियां अरावली श्रृंखला का हिस्सा मानी जायें जिनकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे अधिक हो। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार, पूरी अरावली श्रृंखला में 12,081 पहाड़ियां हैं जिनमें से मात्र 1048 पहाड़ियां ही यानी केवल 8.7 प्रतिशत हिस्सा ही सरकार के 100 मीटर के मानक पर खरी उतरता है। जिस पहाड़ी की ऊंचाई 99 मीटर है, उसे भी सरकार ने पहाड़ी नहीं माना है। कमेटी की अनुशंसाओं से असहमति जताते हुए न्यायमित्र वरिष्ठ वकील के. परमेश्वर ने अरावली श्रृंखला की नई परिभाषा का विरोध किया। उन्होंने कहा था कि भारतीय वन सर्वेक्षण ने इससे पहले अरावली की परिभाषा को लेकर जो नियम बनाये थे, उसके अनुसार, 3 डिग्री से अर्धिाक ढाल, जिसमें घाटियों की चौड़ाई 500 मीटर हो, उसे अरावली श्रृंखला का हिस्सा समझा जाये, इसके अतिरिक्त पहाड़ी के नीचे (तलछटी) में 100 मीटर की चौड़ाई तक किसी भी किस्म की कोई गतिविधि ना की जाये। लेकिन अब तो नया खेल करके सौ मीटर ऊंचाई का मापदंड बना दिया गया है। जिसके बाद इन पहाड़ियों के मनचाहे खनन का खेल खेलने

के लिए मैदान साफ है।कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 4 दिसंबर को द हिंदू में प्रकाशित अपने लेख में इसे श्रअरावली के लिए एक डेथ वारंट यानी मृत्युदंड का ऐलान बताया था। उन्होंने लिखा था कि यह निर्णय उन समूहों के लिए वरदान है जो अवैध खनन और जमीन कब्जे में शामिल रहते हैं। सोनिया गांधी ने याद दिलाया कि अरावली सदियों से उत्तर भारत की जलवायु को संतुलित रखने, थार रेगिस्तान के फैलाव को रोकने और राजस्थान के जंगलों को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि राजधानी दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण अब रोजमर्रा की समस्या नहीं रहा, बल्कि यह एक बड़े जन–स्वास्थ्य संकट का रूप ले चुका है। देश के दस बड़े शहरों में सालाना 30 हजार से अधिक मौतें सिर्फ प्रदूषण की वजह से हो रही हैं।दरअसल केंद्र सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वन संरक्षण नियम 2022 में संशोधन कर प्राकृतिक संसाधनों के गलत तरीके से दोहन का रास्ता खोला है, ताकि कुछ उद्योगपतियों के मुनाफे की हवस पूरी हो सके। इसके बदले भाजपा को करोड़ों

का चंदा मिलता है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी सत्ता बनाए रखने और मनमाने फैसले लेने में करती है। लेकिन माननीय अदालत को यह देखना चाहिए कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए न केवल करोड़ों लोगों को नुकसान में धकेला जा रहा है, बल्कि पर्यावरण को ऐसा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसकी भरपाई संभव नहीं होगी।अगर अदालत को कुछ वक्त बाढ़ यह अहसास होगा कि अरावली पहाड़ों को खत्म करना ठीक नहीं था, तब भी इसका भूल सुधार नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो पहाड़ दो अरब सालों में बने हैं, मजबूत हुए हैं, उन्हें फिर हासिल नहीं किया जा सकेगा। ध्यान रहे कि अरावली पर्वतमाला करोड़ों सालों से थार मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोक रही है। सिंधु–गंगा के उर्वर मैदान को रेगिस्तान बनने से रोक रही है। चंबल, साबरमती और लूनी जैसी नदियों को इन पहाड़ों से जीवन मिला है। करोड़ों साल पुराने एक सम्पूर्ण पारिस्थितिकीय तंत्र को एक इत्थाकथित विशेषज्ञ कमेटिश ने सिर्फ एक शऊंचाईश से परिभाषित कर दिया है, यह बड़ी विडंबना है। अरावली मौसम को संतुलित करने की पुरानी

ढाल है, जिसमें अब जगह–जगह सुराख किए जा चुके हैं। 92 प्रतिशत अरावली को नकारकर हम आने वाली पीढ़ियों के साथ गुनाह करेंगे। मोदी सरकार तो लोककल्याण का मतलब ही भूल चुकी है, उसे न खामोश खड़े जंगल, पहाड़ दिखाई देते हैं, न ही प्रदूषण की त्रासदी से तड़पते लोग दिखते हैं। व्यापारी सरकार को केवल आंकड़े दिखाई देते हैं कि एयर प्यूरीफायर बिकने से कितने का मुनाफा हुआ, दुर्लभ खनिजों की बिक्री से कितने का कमीशन आया। अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के इस खेल को रोक नहीं पाया है। जबकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट की ही बनाई गई एक कमेटी ने पाया था कि अवैध खनन की वजह से राजस्थान में अरावली की 128 पहाड़ियों में से 31 गायब हो चुकी हैं और पहाड़ियों के बीच 10 से अधिक बड़े–बड़े खाली स्थान बन चुके हैं।यह स्थिति भयावह है। गनीमत है कि कांग्रेस के साथ–साथ सपा, आप और बाकी विपक्षी दल भी अरावली को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। यानी इस बार किसी अमृता बिश्नोई को अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा, सियासी दल भी इस बार साथ रह सकते हैं।

टकराया क्योंकि बैकपैक वाला तेजी से मुड़ा और भीड़ में गायब हो गया।मैं खड़ा हुआ तो मेरी सीट भी चली गई। मैं पूरे एयरपोर्ट में घूमता रहा, क्योंकि पूरा पलोर बस स्टैंड से भी बदतर लग रहा था। हर इंच पर यात्री थे, क्योंकि जो स्पेस एक प्लाइट के यात्रियों के लिए भी पर्याप्त नहीं थी, वहां चार अलग–अलग गंतव्यों की चार प्लाइट्स के यात्री थे। इनमें दो डिले प्लाइट्स के यात्री थे और दो शेड्यूल्ड प्लाइट्स के यात्री थे। अगले दो घंटे में उस चेहरे को खोजता रहा, जिसकी झलक कैमरे में दिखी थी, पर ढूँढ़ नहीं पाया। मुझे पता है कि स्कैमर्स अकसर अच्छे कपड़े पहनते हैं और सहज तरीके से बात करते हैं। मैंने

हाट्सएप से लिंकड' हो जाता है। फिर स्कैमर आपकी पहचान बनकर दूसरों से बात कर सकता है। सुरक्षित रहने के लिए अनजान क्यूआर कोड को स्कैन न करें। लिंकड डिवाइसेज की नियमित जांच करते रहें। स्कैमर्स घबराहट और जल्दबाजी पैदा करके फंसाते हैं। मसलन, कोई टोल नाका क्रॉस करते ही वे ट्रैफिक चालान भेज देंगे। लिंक पर क्लिक करने को कहेंगे। पर क्लिक न करें। डर या दबाव लगे तो एक पल रुकें और सोचें। अकसर पहला ट्रैप यही होता है। कभी भी सार्वजनिक अलावों पर अनजान केबल या चार्जिंग पोर्ट से फोन चार्ज न करें। नियमित रूप से डेटा का बैकअप लेकर दूसरे डिवाइस में सुरक्षित रखना भी

कारगर है। ईमेल आईडी, नेट बैंकिंग पासवर्ड कभी नोट्स ऐप, स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप चोट में न रखें। ये साइबर अपराधियों को खुला न्योता है। सार्वजनिक वाई–फाई के इस्तेमाल से बचें। संदिग्ध फोन कॉल पर फैमिली विशेष कोड वर्ड यूज करें। सभी जरूरी अकाउंट्स पर टू–फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू रखना चाहिए। संभव हो तो बैंक अकाउंट से जुड़े फोन नंबर को रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले नंबर अलग रखें, ताकि हैकिंग को रोक सकें। सामान्य नियम यह है कि अनजान नंबर से आए मैसेज या फाइल पर इंटरैक्ट न करें। लिंक पर क्लिक और अटैचमेंट को डाउनलोड न करें, चाहे कितना ही असली लगे।

जानलेवा आबोहवा

देश–दुनिया में दिल्ली में प्रदूषण को लेकर भारी चिंता है, लेकिन यह सिर्फ दिल्ली का ही संकट नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा, उ.प्र. व राजस्थान के कई शहर भी प्रदूषणग्रस्त हैं। इसके अलावा लखनऊ, वाराणसी, जयपुर, पटना, मुम्बफरपुर, कानपुर व देश के अन्य शहरों में भी प्रदूषण संकट आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। हालांकि, इन शहरों में संकट दिल्ली जैसा नहीं है, लेकिन पूरे देश के लिए दीर्घकालीन योजना बनाने की जरूरत तो है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में तीसरे स्थान पर आने वाली दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक का 450 के आसपास बना रहना, निश्चय ही खरेरे की घंटी है। दिल्ली सरकार द्वारा उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम–होम, स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई, तोड़फोड़ व निर्माण पर रोक के बावजूद आशातीत परिणाम सामने नहीं आए हैं। इसी बीच, चीन के दूतावास ने दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण में मदद की पेशकश की है। चीनी दूतावास की एक प्रवक्ता ने एक्स पर पोस्ट में स्क्रीनशॉट साझा किया है, जिसमें दिल्ली में एक्यूआई 447 व बीजिंग में 67 दिखाई दे रहा है। निस्संदेह, भारत व चीन दोनों ही तीव्र शहरीकरण की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। लेकिन चीन ने योजनाबद्ध ढंग से उस परिदृश्य को दूर किया है, जिसमें चीन के तमाम शहर सर्दियों में स्मॉग से ढके रहते थे। हालांकि, साम्यवादी चीन व लोकतांत्रिक भारत में नीतियों के क्रियान्वयन में मूलभूत अंतर है। फिर भी चीन की सफलता से सीखा जा सकता है। चीन ने पिछले दो दशकों में आक्रामक ढंग से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाया। वाहन उत्सर्जन पर नियंत्रण किया। लाइसेंस प्लेट लॉटरी व ऑड–ईवन से सड़कों पर वाहनों को कम किया। उसने बड़े मेट्रो–बस नेटवर्क को बढ़ाकर सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाया। करीब तीन हजार के करीब भारी उद्योगों को बीजिंग व आसपास के शहरों से हटाया गया। एक बड़ी स्टील कंपनी को हटाने से घातक कणों में बीस फीसदी की कमी आई। सबसे अर्धिाक जोर कोयले पर आधारित बिजली संयंत्रों व उद्योगों पर रोक लगाने में लगा। इसके अलावा, निर्माण स्थलों पर धूल–रोधी जाली लगाने, पानी के छिड़काव–सफाई, किसानों को पराली भत्ता देने व प्रदूषण के पीक समय में निर्माण पर रोक जैसे कदम उठाए। वहां पौधारोपण को बढ़ावा दिया गया। निस्संदेह, बीजिंग व दिल्ली की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन बीजिंग मॉडल पर विचार होना चाहिए। दरअसल, दिल्ली की भौगोलिक परिस्थिति बीजिंग से भिन्न है, दिल्ली लैंडलॉक्ड क्षेत्र है, आसपास समुद्री इलाका भी नहीं है। लेकिन कोयला आधारित संयंत्रों को बंद करने, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने तथा औद्योगिक संस्थानों को राजधानी की सीमा से बाहर किया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए विशेष बजट की भी व्यवस्था हो। चिंता की बात यह भी है कि दिल्ली की तीन सौ किमी की परिधि में ग्यारह कोयला आधारित पॉवर प्लांट्स हैं, जिन्हें सर्वाधिक प्रदूषण का स्रोत माना जाता है। बहरहाल, दीर्घकालिक नीति बनाने व फैसलों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है।

श्यामल सेवा समिति ने निराश्रितों को बाटे कंबल

न्यूज वाणी ब्यूरो
इटावा। बढ़ती ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए श्यामल सेवा समिति ने मानवीय संवेदनाओं का परिचय देते हुए गरीब और निराश्रित लोगों की मदद का बीड़ा उठाया है। समिति के निर्णय के अनुसार, रविवार को पचावाली चौराहे के पास फुटपाथ और खुले आसमान के नीचे रात गुजारने वाले जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए।

समिति के सदस्यों ने बताया कि कड़ाके की ठंड में जो लोग बिना गर्म कपड़ों के जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें राहत पहुंचाना ही संस्था का मुख्य उद्देश्य है। वितरण के दौरान सभी सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और भविष्य में भी ऐसे सेवा कार्य जारी रखने का संकल्प लिया। इस सेवा कार्य में समिति की सक्रिय सदस्य स्नेहा पांडे, माला दुबे, नेहा, प्रेमलता, संध्या, अलका, प्रीति शर्मा, प्रतिभा और अंजू ने अपने हाथों से कंबल प्रदान किए। जन सेवा ही नारायण सेवा है श्यामला पांडे भीषण सर्दी को देखते हुए श्यामल सेवा समिति द्वारा आज एक छोटा सा प्रयास किया गया। पचावाली चौराहे के समीप निराश्रित और जरूरतमंद भाइयों-बहनों को कंबल वितरित किए गए। इस पुनीत कार्य में सहयोग देने वाली समिति की सभी कर्मठ सदस्यों स्नेहा पांडे, माला दुबे, नेहा, प्रेमलता, संध्या, अलका, प्रीति शर्मा, प्रतिभा, अंजू आदि मौजूद रहे।

एससीएसटी कानून का लोग कर रहे दुरुपयोग - अब बर्दाश्त नहीं, जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरेगी सवर्ण सेना : प्रभाकर

न्यूज वाणी ब्यूरो
सीतापुर। सवर्ण स्वाभिमान संस्थान सवर्ण सेना के प्रमुख प्रभाकर सिंह चौहान ने एससी/एसटी एक्ट के कथित दुरुपयोग को लेकर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सवर्ण समाज किसी का भी टारगेट पूरा करने का साधन नहीं है और लगातार हो रही प्रताड़ना को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रभाकर सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि वर्तमान समय में सवर्ण समाज के सामान्य नागरिकों के साथ-साथ शिक्षा, चिकित्सा, विकास समेत विभिन्न विभागों में कार्यरत सरकारी एवं संविदा कर्मचारियों को भी एससी वर्ग के कुछ लोग एससीधूसटी एक्ट का भय दिखाकर धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून के नाम पर सवर्ण समाज का मानसिक और आर्थिक शोषण किया जा रहा है। सवर्ण सेना प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया कि कई मामलों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। वहीं, चुने गए जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे गंभीर मामलों में मौन धारण करना उनकी नाकामी को दर्शाता छै श्री चौहान ने आगाह करते हुए कहा कि संगठन अब तक शालीनता और संवैधानिक मर्यादाओं में रहकर अपनी बात रखता आया है, लेकिन यदि उत्पीड़न का सिलसिला नहीं रुका तो सवर्ण समाज को मजबूरन मैदान में उतरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की होगी। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि एससीधूसटी एक्ट का निष्पक्ष और संतुलित प्रयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय न हो और कानून का दुरुपयोग रोका जा सके।

मिशन शक्तिअभियान में महिलाओं-बालिकाओं को बताई योजनाएं



न्यूज वाणी ब्यूरो
सैफई-इटावा। मिशन शक्ति फेज अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में 22 दिसंबर को थाना सैफई पर गठित मिशन शक्ति टीम द्वारा सैफई चौराहा एवं पीजीआई क्षेत्र में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति के उद्देश्यों से अवगत कराते हुए सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं आत्मनिर्भरता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारीयों प्रदान की गई। मिशन शक्ति टीम द्वारा महिलाओं व बालिकाओं को पंपलेट वितरित कर विभिन्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंदांरों, साइबर अपराध से बचाव, तथा आपातकालीन सेवाओं की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें यह बताया गया कि किसी भी प्रकार की समस्या या आपात स्थिति में तुरंत संबंधित हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। इस अवसर पर महिलाओं एवं बालिकाओं को महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं जैसे विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आयुष्मान भारत, पीएमजेएवाई स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं नशा मुक्ति भारत अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मिशन शक्ति टीम द्वारा छात्राओं को शिक्षा को प्राथमिकता देने, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उज्ज्वल भविष्य निर्माण तथा सीखी गई जानकारीयों को परिवार एवं समाज में साझा करने का संदेश दिया गया। अभियान के अंत में मिशन शक्ति टीम ने यह संदेश दिया कि स्वस्थ और सतर्क रहना ही असली सुरक्षा है।

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उत्तर प्रदेश महिला सम्मान से जुड़ी घटना पर IUML का कड़ा विरोध, जिलाधिकारी लखनऊ को सौंपा गया जापन



(संवाददाता) लखनऊ। कि यह घटना न केवल एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महिला की गरिमा को ठेस

ने बिहार में दिनांक 15 दिसंबर 2025 को एक महिला आयुष डॉक्टर को नियुक्ति पत्र प्रदान करते समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई कथित अमद्र एवं अमर्यादित हरकत की कड़ी निंदा की है। पार्टी का कहना है

पहुँचाती है, बल्कि देश की समस्त महिलाओं के सम्मान पर गंभीर आघात है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जिला अध्यक्ष श्री मंसूर अजीम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने

न्यूज वाणी ब्यूरो
हरगांव, सीतापुर। ब्लॉक हरगांव में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विजय भार्गव के नेतृत्व में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम हटाए जाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष डॉ. ममता वर्मा पासी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के अंतर्गत कांग्रेस ब्लॉक कार्यालय से सैकड़ों मनरेगा मजदूरों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं हरगांव की जागरूक जनता के साथ एक विशाल जुलूस निकाला गया। जो विभिन्न मार्गों से होते हुए खंड विकास कार्यालय परिसर स्थित बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर पार्क पहुँचा। वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया

पावन धरती पर पधार रहे पूज्य संत राजेंद्रदास जी महाराज

न्यूज वाणी ब्यूरो
इटावा। श्री राम चरित मानस में गोस्वामीजी लिखते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता अर्थात



जब जीवन के अनेक पुण्य पुंज यानी समूह बनकर उदय होते हैं, तब व्यक्ति को किसी महान पूज्य संत का दर्शन और सानिध्य मिलता है और ऐसा ही सौभाग्य इटावा के भक्तमना लोगों को मिलने जा रहा है। इष्टिकापुरी इटावा की पावन धरती पर भारत



पर शनिवार देर शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब शराब के नशे मेंधुत एक डॉक्टर ने सड़क

न पहले ऑटो चालकों से अमद्रता की और बाद में वहां मौजूद आम लोगोंसेभी उलझते रहे। प्रत्यक्षदर्शियों

न्यूज वाणी ब्यूरो
इटावा। 24 दिसंबर को अटल प्रतिमा का अनावरण दोपहर 2 बजे होगा। एक माह पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के तहत 24 दिसंबर को भारत रत्न, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का भव्य अनावरण एवंअटल पथ का लोकार्पण

जिलाधिकारी लखनऊ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से महिला सम्मान की रक्षा तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की माँग की गई। इस अवसर पर डॉ. मोहम्मद मतीन खां (प्रदेश अध्यक्ष, प्जड्स उत्तर प्रदेश) विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ मोहम्मद साद प्रदेश महाचिव (उॅी ,मोहम्मद समि एडवोकेट, गुफरान अहमद खां, सुलेमान खां सहित इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी ने कहा कि इस घटना के बाद देश की आम महिलाएँ स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। साथ ही, सत्ताधारी दल से जुड़े कुछ नेताओं द्वारा दिए गए



कि देश को रोजगार चाहिए, नाम बदलने की राजनीति नहीं। हीं कांग्रेस उपाध्यक्ष जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि मनरेगा केवल योजना नहीं, बल्कि सम्मान, रोजगार और अधिकार का प्रतीक है। आज के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से हरगांव ब्लॉक प्रभारी अनिल दीवान,

सीताराम भार्गव, अतुल भार्गव, अनिल कुमार उमाशंकर, राजकिशोर भार्गव, रमेश भार्गव, सुनील भार्गव, ओमान रियाज, मिटू राजकुमारी, चंद्रकली, संतोष भार्गव, शबनम, सूरज सहित सैकड़ों मनरेगा कर्मचारी एवं कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

जो का जन्म मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के अचर्रा ग्राम में एक शुद्ध सनातनी ब्राह्मण परिवार में हुआ जो अपने बाल्यकाल से ही भगवदभजन हेतु वृंदावन आ गए थे, जहां सबसे पहले उन्हें विख्यात संत भक्तमाली जी का सानिध्य मिला, इसके बाद सिद्ध संत पहाड़ी बाबा जी से उन्होंने दीक्षा लेकर सनातन धर्म, शास्त्र और गौसेवा के प्रचार प्रसार हेतु अपना जीवन समर्पित कर दिया।वर्ष 2018 में उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा षविद्या वाचस्पतिष की मानद उपाधि से विभूषित किया गया।वे भारत के सर्वाधिक पूज्य संत की मान्यता रखते हैं।अभी हाल ही में जब वे वृंदावन के केली कुंज आश्रम में रह रहे संत प्रेमानंद जी के स्वास्थ्य का हालचाल जानने उनके पास गए तो पूज्य प्रेमानंद जी ने भी उनके चरण प्रक्षालन कर उनका वंदन अभिनंदन किया।[पूज्य मलूक पीठाधीश्वर जी के द्वारा हजारों साधु संतों, गरीबों को भोजन वस्त्र,

केअनुसार कार चालक डॉक्टर काफी देर तक सड़क पर वाहन खड़ा किए रहे, जिससे यातायात बाधित हो गया। ऑटो चालकों द्वारा विरोध करने पर डॉक्टर साहब उनसे भिड़ गए और गाली-गलौज करने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने जब उन्हें समझाने का प्रयास किया तो उनके साथ भी अमद्र व्यवहार किया गया। बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर जब लोगों ने कैमरा चालू किया तो डॉक्टर का नशा मानो उतर गया। इसके बाद वह जल्दबाजी में कार स्टार्ट कर मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार हंगामा करने वाले व्यक्ति का नाम डॉक्टर सुर्ख सिंह बताया जा रहा है,

कसें। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आयोजन स्थल पर जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों एवं आमजन की उपस्थिति अपेक्षित है। यह कार्यक्रम जनपद के लिए गौरव का

जो पूर्व में पीएचसी भोखेला पर तैनात रह चुके हैं। इसकेअलावा वह सीएचसी ढूंढला पर नाइट डॉक्टर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। घटना के समय कार में डॉक्टर के साथ दो अन्य साथी भी मौजूद थे। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि, इस मामले में अब तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने ऐसे गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान वहां विकास जैन, रवि कुमार, सत्येंद्र कुमार आदि लोग मौजूद रहे।

कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरु हुआ वार्षिक खेलकूद



न्यूज वाणी ब्यूरो
इटावा। चार दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा उत्सव का आयोजन बैंक ऑफ बडौदा के सौजन्य से शुभारंभ हुआ। जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर .षि इंजीनियरिंग कॉलेज, दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, मत्स्य महाविधालय के विद्यार्थियों ने विभिन्न खेल प्रतियोगताओं में संयुक्त रूप से प्रतिभाग करेंगे। उदघाटन के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि ज्योति गुप्ता, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद ने अपने संबोध्ान में कहा कि खेलों से विद्यार्थियों का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है जिससे उनका सर्वांगीण विकास होता है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आनंद मोहन ने भी विद्यार्थियों के चोमुखी विकास के लिए विद्यार्थियों को खेल प्रतियोगताओं में भाग लेने का आहवान किया। गेस्ट ऑफ ऑनर दिनेश गौर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने भी विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास पर प्रकाश डाला। इंजीनियरिंग कॉलेज के डीन डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने महाविद्यालय में शैक्षिक माहौल के साथ साथ विद्यार्थियों को खेल प्रतियस्पर्ा में भी भाग लेने का आहवान किया और साथ साथ यह भी कहा कि महाविधालय में विद्यार्थियों को हर स्तर भर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम के शुभ अवसर पर वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर जेपी यादव, डॉक्टर अजीत सिंह, डॉक्टर के के पटेल, डॉ टीके माहेश्वरी, इंजी. दिलीप वर्मा, डॉ आशीष कुमार, डॉ अरुण कुमार, डॉ आशुतोष का कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग रहा। अंत में सत्येंद्र पाल डायरेक्टर शारीरिक शिक्षा ने खेल प्रतिस्पर्धाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई एवं अतिथियों का आभार व्यक्त किया।

जनसुनवाई में एसएसपी ने अधिकारियों से की वार्ता, कार्रवाई के आदेश

न्यूज वाणी ब्यूरो
इटावा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनसुनवाई में सुनीं फरियादियों की समस्याएं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस कार्यालय में नियमित रूप से आयोजित जनसुनवाई के



दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना गया। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त प्रार्थना पत्रों (शिकायतों) पर प्रभावी एवं त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधित राजपत्रित पुलिस अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्वयं संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर प्रत्येक शिकायत का न्यायोचित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किए जाने का आश्वासन फरियादियों को दिया। एसएसपी ने कहा कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि पुलिस और जनता के बीच विश्वास को और अधिक मजबूत किया जा सके।

राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति की बैठक में कार्य समिति का विस्तार

न्यूज वाणी ब्यूरो
इटावा। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति की बैठक जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह कुशवाह की अध्यक्षता मेंरेंड्रस कॉलोनी स्थित मंडल अध्यक्ष उत्तम सिंह प्रजापति के आवास पर आयोजित की गई। बैठक का संचालन जिला प्रभारी धर्मेन्द्र जैन ने किया। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गेश सिंह सेंसर द्वारा जारी किए गए। समिति के प्रमाण पत्र एवं पहिचान कार्ड वितरण करके



सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रदेश संगठन मंत्री, जिलाध्यक्ष नरेन्द्र सिंह कुशवाह एवं मंडल अध्यक्ष उत्तम सिंह प्रजापति ने सभी पदाधिकारियों को सम्मानित किया। इस मौके पर मंडल प्रभारी सन्तोष कुमार राजपूत, महिला जिलाध्यक्ष अर्चना कुशवाह, महामंत्री पंकज कुशवाह, जिला उपाध्यक्ष लल्लू वारसी, जिला उपाध्यक्ष विकास शाक्य, जिला मीडिया प्रभारी इकरार अहमद, शहर अध्यक्ष रंजीत सिंह कुशवाह आदि मौजूद रहे।

दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

न्यूज वाणी ब्यूरो
फिरोजाबाद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद मे चलाये जा रहे विशेष

अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा दौराने देख रेख शान्ति व्यवस्था, चेकिंग अभियुक्तगण अजय पुत्र जाहर सिंह निवासी टूटी पुलिया आसफाबाद थाना रसूलपुर व सतेन्द्र उर्फ भीमा पुत्र देवीराम निवासी सतीनगर आसफाबाद थाना रसूलपुर को आसफाबाद बिजलीधर के पास से गिरतार किया गया।

अदालत को गुमराह करना प्रधान को बड़ा भारी – अदालत ने जारी किया वारंट, नेरी का प्रधान अब जाएगा जेल

न्यूज वाणी ब्यूरो
सीतापुर। ब्लाक पिसावा के अंतर्गत ग्राम पंचायत नेरी का प्रधान नूर हसन अदालत को बारंबार गुमराह कर रहा था। 22 दिसंबर को भी नूरहसन



द्वारा अदालत का समय जाया किया। नूरहसन अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। नूरहसन के उपस्थित न होने से विद्वान न्यायाधीश जूनियर डिवीजन द्वितीय ने पुलिस को वारंट जारी करने का आदेश देकर 16 जनवरी को अदालत में पेश किए जाने को कहा है। विदित हो कि नेरी का प्रधान नूरहसन एक मामले में गवाह था। 2007 से मामला अदालत में विचाराध् पीन है। इतने लम्बे अंतराल से नूरहसन गवाही नहीं दे रहा था तब इसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया। इसके पहले भी नूरहसन वारंट की वजह से ही अदालत मेंआधी गवाही देकर बीमार होने का नाटक कर भाग गया था। उसके बाद अनेक तारीखों पर नहीं पहुंचा। नूरहसन की हठधर्मिता का आलम यह है कि गांव वालों के साथ नाइंसाफी करते करते अदालत को भी गुमराह करने का काम करने लगा है। तब विद्वान न्यायाधीश ने वारंट जारी कर पुलिस को निर्देश दिया है कि अगली तारीख पर नूरहसन को पकड़कर अदालत के सम्मक्ष पेश किया जाए।

एटी करणन की टीम ने बीईओ व सहायक अध्यापक को रिश्वत लेते पकड़ा

न्यूज वाणी ब्यूरो
शाहजहांपुर। भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली की टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अभियुक्त सतीश कुमार मिश्रा खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड कलान व सुशील कुमार सिंह सहायक अध्यापक कलान को 5000 की रिश्वत लेते हुए गिरतार कर लिया। कलान प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक डब्लू कुमार पुत्र स्वर्गीय कालीचरण ने भ्रष्टाचार निवारण समिति से शिकायत की थी कि ड्यूटी से अनुपस्थित अवधि को निस्तारण करने की एवज में 5000 की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायतकर्ता की शिकायत का संज्ञान लेकर भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली की टीम द्वारा नियमानुसार तत्काल कार्यवाही करते हुए सतीश कुमार मिश्रा खंड शिक्षा अधिकारी व सुशील कुमार सहायक अध्यापक को 5000 की रकम लेते रहे ग्थाओं गिरतार कर लिया। बरेली मंडल बरेली का कोई भी पीडित व्यक्ति पुलिस उपाधीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली के मोबाइल नंबर 9454406475 एवं प्रमारी निरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली इकाई थाना के मोबाइल नंबर 94544001653 पर संपर्क कर सकता है।

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, युवक पर मुकदमा दर्ज

न्यूज वाणी ब्यूरो
/अटरिया, सीतापुर। सिधौली कोतवाली अंतर्गत अटरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना सामने आई है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने बहादुरापुर गांव निवासी राहुल पुत्र सानू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने का दावा सूत्रों के अनुसार युवक और नाबालिग किशोरी को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया था। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। घटना की जानकारी होने पर परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और सख्त कार्रवाई की मांग की। परिजनों की तहरीर पर दर्ज हुआ केस मामला सामने आने के बाद पीड़िता के परिजन अटरिया थाने पहुंचे और युवक के खिलाफ लिखित तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रेप जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीत कर लिया। पीड़िता का मेडिकल, आरोपी की तलाश तेज थाना प्रमारी निरीक्षक राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी की गिरतारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं और जल्द ही उसे हिरासत में लिया जाएगा।

सहायक अध्यापक ने बच्चों को स्वेटर व टोपी की वितरित

न्यूज वाणी ब्यूरो
/मऊ। जनपद के बडराव ब्लाक के शिक्षा क्षेत्र बडराव के कम्पोजिट विद्यालय बनियापार बडराव के सहायक अध्यापक विवेक कुमार रान्ू द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं को स्वेटर और टोपी



वितरित किया गया। कम्पोजिट विद्यालय बनियापार के करीब 50 छात्र छात्राओं को स्वेटर और टोपी वितरित किया गया। बढ़ते ठंड को देखते हुए कम्पोजिट विद्यालय बनियापार के सहायक अध्यापक विवेक कुमार रान्ू द्वारा बढ़ते हुए ठंड को देखते हुए स्वेटर और टोपी दिए जिससे कि बच्चों को ठंड से राहत मिल सके और पठन पाठन की क्रिया सुचारु रूप से चलती रहे। इसके लिए आज विवेक कुमार रान्ू सहायक अध्यापक द्वारा अपने विद्यालय कम्पोजिट विद्यालय बनियापार बडराव ने अपने निजी खर्च से बच्चों को स्वेटर और टोपी वितरित किया गया। स्वेटर और टोपी पाकर बच्चे खुशी से झूम उठे। उनका यह पुनीत कार्य सराहनीय, प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है। वितरण कार्यक्रम मेंसूर्यप्रताप सहायक अध्यापक, सावित्री देवी शिक्षा मित्र, मनेज कुमार गुप्ता, सहायक अध्यापक, अंकित कुमार अनुचर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। विवेक कुमार रान्ू के इस पुनीत कार्य को विद्यालय के सभी अध्यापक एवं अन्य लोगों ने विवेक कुमार रान्ू की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके इस कार्य से विद्यालय में सभी छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल बना हुआ है।

मदरसा पोर्टल पर फार्म भरने की समय-सारणी का हुआ निर्धारण

न्यूज वाणी ब्यूरो
मऊ। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा अरगी तथा फारसी की मुशी, मौलवी (सेकेण्डरी फारसी, अरबी), आलिम (सीनियर सेकेण्डरी फारसी, अरबी) परीक्षा वर्ष 2026 के परीक्षा आवेदन पत्रों को मदरसा पोर्टल पर भरने से सम्बन्धित समय–सारण निर्धारित की गयी है। मदरसे के प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्या द्वारा छात्र–छात्राओं का परिषद की मुंशी: मौलवी (रोकेण्डरी फारसी अरबी), आलिम (सीनियर सेकेण्डरी फारसी

जंगली जानवर की आहत से दहशत, खेतों में मिले रहस्यमय पदचिह्न - वन विभाग अलर्ट, किसानों को समूह में खेत जाने की सलाह

न्यूज वाणी ब्यूरो
लहरपुर, सीतापुर। लहरपुर क्षेत्र में अज्ञात जंगली जानवर के पदचिह्न मिलने से ग्रामीणों में भय और चिंता का माहौल बन गया है। खेतों में मिले पदचिह्नों के बाद लोग रात में पहरा देने को मजबूर हैं, वहीं वन विभाग भी सतर्क हो गया है। जानकारी के अनुसार, शनिवार देर रात ग्राम लच्छन नगर निवासी सरदार बलदेव सिंह ने खेत की रखवाली के दौरान टॉर्च की रोशनी में दो जंगली

जिले में शुक्रना यात्रा आने पर हुआ जोरदार स्वागत - श्रद्धालुओं व संगत के लिए लंगर की हुई उत्तम व्यवस्था

न्यूज वाणी ब्यूरो
फतेहपुर। शहर में नवम फतेहपुर श्रद्धालुओं व संगत के रूप में वर्मा चौराहा से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा



साहिब जी के 350 वें शहीदी दिवस पर आयोजित शुक्राना यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यह पावन यात्रा गुरुद्वारा साहिब धुबड़ी असम से चलकर फतेहपुर पहुंची। यात्रा नगर

तक पहुंची। मार्ग में नगर के अनेक स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा कर यात्रा का सम्मान किया गया। गुरुद्वारा परिसर में यात्रा में सम्मिलित श्रद्धालुओं एवं संगत के लिए लंगर की उत्तम

मनरेगा के निरस्तीकरण को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

- गांधी दर्शन के आगे विश्व नतमस्तक : महेश द्विवेदी

न्यूज वाणी ब्यूरो
फतेहपुर। भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदल कर जी राम जी करने एवं योजना के अंतर्गत मजदूरों के भुगतान का चालीस प्रतिशत राज्य सरकार के ऊपर थोपने को लेकर सोमवार को जिला एवं शहर के कांग्रेसियों ने कचेहरी पहुंच कर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष महेश द्विवेदी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मनरेगा का मुख्य उद्देश्य हर हथंथ को काम एवं काम के बदले दाम देना था जिससे ग्रामीण मजदूरों को काम की गारंटी हो व उनके जीवन यापन में सुधार आए जिसे अब खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि आज पूरा विष्व गांधी जी के विचारों का सम्मान करते हुए गांधी दर्शन के आगे नतमस्तक है परंतु दु:ख है कि उनके ही देश में अपने थोड़े से राजनैतिक लाभ के लिए स्वार्थी भाजपा उनका अनादर कर रही है एवं उनके हत्यारे गंडसे का महिमा मंडन कर रही है जो अत्यंत घृणित है। वरिष्ठ नेता शेख एजाज अहमद ने कहा कि इतिहास गवाह है कि सत्ता का मद सत्ता का सर्वनाश कर देती है जो भविष्य में जनता देखेगी वहीं वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह एडवोकेट ने भी भाजपा की ओछी राजनीति की आलोचना की।

नीति आयोग के सहयोग से डिजिटल हुआ राजकीय जिला पुस्तकालय - अपग्रेडेशन कर पाठकों के लिए सुविधाओं का हुआ विस्तार



स्थान पर न्यूनतम शुल्क पर प्रतियोगी छात्रों को आफलाइन व आनलाइन अध्ययन सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है। उल्लेखनीय है कि राजकीय जिला पुस्तकालय के अपग्रेडेशन कार्य में सबसे बड़ी चुनौती पूर्व में स्थापित लाइब्रेरी में रखी हुयी पुस्तकों, फर्नीचर व अलमारी को हटाकर रिनोवेशन कराना था। परन्तु तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए पाठकों की सुविधा के लिए राजकीय जिला पुस्तकालय को वातानुकूलित करने के साथ–साथ पुस्तकालय को डिजिटली अपग्रेड करते हुए वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। यहां पर आने वाले पाठकों के लिए आफलाइन व आनलाइन पुस्तकों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी। राजकीय जिला पुस्तकालय डिजिटली अपग्रेड होने से गरीब एवं मेधावी छात्रों को न्यूनतम शुल्क के साथ आधुनिक सुविधाओं सहित आफलाइन व आनलाइन अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो रही है।

की अन्तिम तिथि 20 दिसंबर मदरसे के प्रधानाचार्य प्रधानाचार्या द्वारा छात्र–छात्राओं के आवेदन पत्रों को नियमानुसार मदरसा पोर्टल पर लॉक करने की अन्तिम तिथि 22 दिसंबर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों को आनलाइन मदरसा पोर्टल पर सन्देहास्पद बाटा को सम्मिलित करते हुए लाक करने की अन्तिम तिथि 26 दिसंबर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिाकारी द्वारा परीक्षा वर्ष 2026 हेतु परीक्षा केंद्रों के डाटा फीड किये जाने के उपरान्त परीक्षा केंद्रों पर सम्मिलित होने वाले मदरसों की आनलाइन मदरसा पोर्टल पर मैपिंग की अवधि 1 06 जनवरी 2026 से 12 जनवरी तक, परीक्षा वर्ष 2026 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र, उपस्थिति पत्रक एवं डेस्क–स्लिप जारी किये जाने की तिथि 15 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है।

सोमवार को वन क्षेत्राधिकारी अभिषेक सिंह ने भी प्रभावित गांवों का दौरा किया। उन्होंने बताया कि मिले पदचिह्न चार–पांच दिन पुराने प्रतीत होते हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर ग्रामीणों को पूरी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इस घटना के बाद मोहल्ला अंबर सराय में किसान लाठी–छंडे लेकर तहसील के पीछे अपने खेतों की रखवाली करते नजर आए। वन विभाग ने किसानों को अकेले खेतों में न

जानवरों को देखा। रविवार सुबह गेहूं के खेत में जंगली जानवर के स्पष्ट पदचिह्न मिलने पर उन्होंने गांव के किसानों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद मोहल्ला अंबर सराय निवासी किसान रत्नेश तिवारी और ग्राम सुल्तानपुर हर प्रसाद के किसान राहुल मिश्रा के खेतों में भी ऐसे ही पदचिह्न पाए गए। सूचना मिलने पर वन दरोगा राजकुमार वर्मा और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पदचिह्नों का निरीक्षण किया।

जिले में शुक्रना यात्रा आने पर हुआ जोरदार स्वागत - श्रद्धालुओं व संगत के लिए लंगर की हुई उत्तम व्यवस्था

व्यवस्था की गई, जिसमें बड़ी संख्या में संगत ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर दीपक रस्तोगी ने वर्मा चौराहा पर चाय–नाश्ते की व्यवस्था की। मनोज घायल ने आतिशबाजी का आयोजन किया। पाँच प्यारों को दूध पिलाकर सम्मानित किया। सत्य भगवान ने मोतियों की माला पहनाकर सत्कार किया। व्यापार मंडल के संस्थापक अध्यक्ष किशन मेहरोत्रा ने यात्रा का स्वागत किया। समस्त कार्यक्रम श्रद्धा, अनुशासन एवं गुरु मर्यादा के अनुरूप शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ। नगर की संगत में इस पावन अवसर को लेकर विशेष उत्साह एवं श्रद्धा का वातावरण देखने को मिला। इस

प्रदर्शन में महिला नेता संतोष कुमारी शुक्ला, श्रवण कुमार गौड़, देवी



प्रकाश दुबे, सईद चच्चा, ओम प्रकाश कोरी, मणि प्रकाश दुबे, राम नरेश महाराज, आशीष गौड़, आनंद गौतम, पप्पी राजपूत, शकीला बानो, पूनम द्विवेदी, सैयद सहाब अली, अमरनाथ कैथल, चौधरी

खान, पुष्पराज मिश्र, हिमांशु दीक्षित, अमय शुक्ला, नवनीत तिवारी, नौशाद अहमद, अमर यादव, नवनीत तिवारी, राजीव श्रीवास्तव, अजय बच्चा, चंद्रेश कुमार, कल्लू कोरी, आदि लोग मौजूद रहे।

प्रकाश दुबे, सईद चच्चा, ओम प्रकाश कोरी, मणि प्रकाश दुबे, राम नरेश महाराज, आशीष गौड़, आनंद गौतम, पप्पी राजपूत, शकीला बानो, पूनम द्विवेदी, सैयद सहाब अली, अमरनाथ कैथल, चौधरी

न्यूज वाणी ब्यूरो
बहराइच। जनपद स्तर पर प्रतियोगी छात्रों के लिए अध्ययन हेतु डिजिटली सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से नीति आयोग भारत सरकार से वर्ष 2023 में प्राप्त हुई धनराशि 103.65 लाख से गेंद घर मैदान स्थित राजकीय जिला पुस्तकालय को डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में विकसित करने के साथ साथ पाठकों के लिए सुविध्ाओं का विस्तार किया गया है। डिजिटल लाइब्रेरी स्थापना से एक

मदरसा बोर्ड के आवेदन की अन्तिम तिथि बढ़ कर हुई 26 दिसंबर

न्यूज वाणी ब्यूरो
बहराइच। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मो. खालिद ने बताया है कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा संचालित मुन्शीध्मोलवी (सेकेण्ड्री) तथा आलिम (सीनियर सेकेण्ड्री) परीक्षा वर्ष 2026 के ऑनलाइन आवेदन–पत्र की अन्तिम तिथियां में संशोधन किया गया है। अब चालान के माध्यम से राजकोष में परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि 24 दिसम्बर होगी तथा 26 दिसम्बर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन–पत्र भेरे जा सकेंगे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने यह भी बताया कि यदि किसी मदरसा द्वारा परीक्षा वर्ष 2026 के परीक्षा आवेदन पत्र नहीं भरवाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध उ. प्र. अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन एवं सेवा विनियमावली 2016 में निहित व्यवस्थान्तर्गत कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए सम्बन्धित मदरसा प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य स्वयं उत्तरदायी होंगे।

युवक पर धारदार हथियार से हमला, मरणासन्न हालत में खेत में फेंका

न्यूज वाणी ब्यूरो
रामकोट, सीतापुर। रविवार देर रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। थाना रामकोट क्षेत्र के खटकरी खुर्द गांव में एक युवक पर धारदार हथियार से ताबझोड़ हमला कर उसे मृत समझकर खेत में फेंक दिया गया। गंभीर रूप से घायल युवक किसी तरह होश में आया और जान बचाने के लिए घिसटता हुआ अपने घर पहुंचा। घटना में घायल युवक की पहचान ओमकार के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार आरोपियों ने उसे घर से बुलाया और खेत में ले जाकर जानलेवा हमला किया। हमलावरों ने उसके सिर पर कई बार किए, कान काट दिया और गला ढंत्ने का भी प्रयास किया। युवक को मरा समझकर हमलावर मौके से फरार हो गए। कुछ समय बाद होश में आने पर ओमकार किसी तरह खुद को संभालते हुए घर पहुंचा। रूतू से लथपथ हालत में उसे देखकर परिजनों के होश उड़ गए। आनन–फानन में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया। पीडित के परिजनों ने शीघ्र के देवगनपुर गांव के ग्राम प्रधान महेश पर घटना में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते इस खौफनाक वारदान को अंजाम दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि पीडित के बयान और परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। इस सनसनीखेज घटना के बाद गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है। लोग सुख्खा को लेकर सहम हुए हैं और जल्द आरोपियों की गिरतारी की मांग कर रहे हैं।

देर रात महत्वपूर्ण ब्लैक स्पॉट्स का डीएम ने किया निरीक्षण

न्यूज वाणी ब्यूरो
मऊ। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने कल देर रात सड़क सुख्खा के ष्टिगत बलिया मोड़ से देहरीघाट तक के महत्वपूर्ण ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण किया। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण गोरखपुर एवं आजमगढ़, लोक निर्माण विभाग, यातायात पुलिस, परिवहन विभाग एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों सहित कई संबंधित विभागों के अधिकारी भी साथ रहे। जिलाधिकारी ने बलिया मोड़, सेल्फी प्वाइंट, कसारा मोड़, कोमगंज, घोसी एवं देहरीघाट के रास्ते पर पड़ने वाले लिंक रोड एवं महत्वपूर्ण कट का भी निरीक्षण किया। इन स्थलों को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। ज्ञातव्य है कि गत दिनों सड़क सुख्खा समिति की बैठक के दौरान सेवा फाउंडेशन द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे जिसके ष्टिगत जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यदाई संस्थाओं एवं विभाग के अधिकारियों के साथ देर रात इन महत्वपूर्ण ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर की जाने वाले आवश्यक कार्यवाहियों के बारे में जानकारी लेते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं एवं उनमें होने वाली मौतों में तेजी से कमी लाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिाकरण एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को यथाशीघ्र हो सकने कार्यों को तत्काल करने को कहा। साथ ही लंबे समय में होने वाले कार्यों हेतु शीघ्र ही कार्य योजना तैयार कर उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह सहित सड़क सुख्खा से जुड़ समस्त विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।

जल जीवन मिशन में तीन साल से पाइपलाइन अधूरी, सड़कें क्षतिग्रस्त

न्यूज वाणी ब्यूरो
सीतापुर। विकास खंड स्थित ग्राम पंचायत घरैली में जल जीवन मिशन का कार्य अधूरा पड़ है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि तीन साल पहले पानी की टंकी बनने के बावजूद पाइपलाइन का काम पूरा नहीं हुआ है जिससे लोगों को पेयजल संकट और क्षतिग्रस्त सड़कों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। रवि कुमार पुत्र कुलीधर निवासी घरैली ने बताया कि एलएनटी कम्नी द्वारा ग्राम पंचायत घरैली और संबंि त मजरों में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का निर्माण 2022 में पूरा कर लिया गया था। हालांकि, इसके बाद डाली गई पाइपलाइन का काम आज तक अधूरा है। ग्राम पंचायत के पांच मजरों में आरसीसी सड़कें पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई थीं, जो अब तक मरम्मत नहीं की गई हैं। इन खुदी हुई सड़कों और पानी के लीकेज के कारण आवागमन में भारी पेशानी हो रही ग्रामीणों के अनुसार, पिछले तीन सालों से न तो पानी की आपूर्ति पूरी हो पाई है और न ही क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की गई है। इस संबंध में कई बार शिकायत करने के बावजूद संबंि त कर्मचारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है जिससे समस्या का समाध्ान नहीं हो पा रहा है ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द से जल्द इस समस्या का समाध्ान करने और आरसीसी सहित अन्य सड़कों की मरम्मत कराने की मांग की ।



राष्ट्रपति को संबोधित ज़ापन जिलाधिकारी को सौंपा

न्यूज़ वाणी ब्यूरो
इटावा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के निर्देशानुसार जिलाध्यक्ष आशुतोष दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने कचहरी परिसर में मनरंगा योजना से महात्मा गांधी जी का नाम हटाए जाने को लेकर निरोध प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज़ापन सौंपा।

राष्ट्रपति को संबोधित ज़ापन में जिलाध्यक्ष आशुतोष दीक्षित ने कहा कि जनता को हर अधिकार से वंचित करने का घृणित षडयंत्र भाजपा सरकार कर रही है। इसी दिशा में दिहाड़ी मजदूरों की रोजी रोटी छीनने का भी प्रयास शुरू हो गया है। इसीलिए भाजपा सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधि नियम (मनरेगा) को निरस्त करना बहुत खिंताजनक है। इसी क्रम में शहर अध्यक्ष मोहम्मद राशिद ने कहा मनरेगा को निरस्त करने के लिए विधेयक पेश करने का कार्यक्रम भाजपा का एक अत्यन्त सुनियोजित कदम है। जिसे गरीबों के हक में कांग्रेस पार्टी कभी पूरा नहीं होने देगी। ज़ापन में पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि यह कोई सामान्य विधायी प्रक्रिया नहीं है, यह एक ऐतिहासिक, अधिकार–आधारित जन कल्याण कारी कानून को निरस्त कर देश के गरीब मजदूरों का अधिकार छीनना है। कांग्रेस जनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आवाज बुलंद की यदि भाजपा सरकार ने मनरेगा निरस्त विधेयक वापस नहीं लिया तो कांग्रेस पार्टी समूचे देश में क्रांतिकारी आंदोलन करने को बाध्य होगी। प्रदर्शन करने वालों में प्रमुख रूप से पूर्व जिला अध्यक्ष मलखान सिंह यादव, पूर्व शहर अध्यक्ष पल्लव दुबे, कोमल सिंह कुशवाहा, करन सिंह राजपूत, प्रशांत तिवारी, वाचस्पति द्विवेदी, सतीश नागर, संजय दोहरे, कुसुम लता उपाध्याय, विष्णु कांत मिश्रा, मोहनलाल प्रजापति, .पाराम राजपूत, सुनीता कुशवाहा, आशाराम कठेरिया, नरेंद्र यादव, सतीश शाक्य, प्रदीप द्विवेदी, दीक्षा शुक्ला, सुहेल एवं अंसार अहमद सहित तमाम कांग्रेस जन उपस्थित रहे।

वर्षों का इंतजार खत्म, कन्हई घाट पुल को मिली मंजूरी

- 10 करोड़ की पहली किस्त स्वीकृत

न्यूज़ वाणी ब्यूरो
सीतापुर। जनपद के रामपुर मथुरा क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। कन्हई घाट पुल के निर्माण को आखिरकार हरी झंडी मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बहुमतीक्षित परियोजना के प्रथम चरण के लिए 10 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीत कर दी है।



पुल की कुल अनुमानित लागत करीब 28 करोड़ रुपये बताई जा रही है। रविवार को सेवता विधायक ज्ञान तिवारी को इस स्वी.ति की आधिकारिक जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के मा् यम से क्षेत्रवासियोंको खुशखबरी दी। वर्षों से अधूरा पड़ा यह

पुल स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था, खासकर

बरसात के मौसम में आवागमन बेहद कठिन हो जाता था। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कनरखी निवासी सोनू कुमार निषाद ने भी इस पुल के निर्माण के लिए विधायक ज्ञान तिवारी से कई बार आग्रह किया था, जो अब रंग लाता दिखाई दे रहा है। पुल के निर्माण से रामपुर मथुरा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में यातायात व्यवस्था सुगम होगी। इसके साथ ही व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी, जिससे क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। इस घोषणा से क्षेत्रवासियोंमें खुशी की लहर है। स्थानीय जनप्रतिनिधियोंऔर नागरिकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।

गृहकर-जलकर के 40 बड़े बकायेदारों के नाम सार्वजनिक

न्यूज़ वाणी ब्यूरो
सिधौली, सीतापुर। सिधौली नगर पंचायत कार्यालय ने गृहकर और जलकर की वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए बड़े बकायेदारों के खिलाफ सार्वजनिक कार्रवाई की है। नगर पंचायत कार्यालय की दीवारों पर 20–20 नामों वाले दो विशाल बैनर लगाकर कुल 40 बकायेदारों के नाम उजागर किए गए हैं। खास बात यह है कि इस सूची में निजी संस्थानों के साथ–साथ कई सरकारी कार्यालय और प्रतिष्ठित संस्थान भी शामिल हैं। सूची में सबसे बड़ा बकायेदार ताराचंद अनय कुमार ब्रिक फील्ड है, जिस पर 6,15,252 का गृहकर व जलकर बकाया है। इसके अलावा तहसीलदार कार्यालय सिधौली पर 1,72,800, केतवाली सिधौली पर 1,45,200 और 33 / 11 कैंची विद्युत पावर हाउस पर 1,38,240 का बकाया दर्ज है। अन्य प्रमुख बकायेदारों में श्री गंधी विद्यालय इंटर कॉलेज छात्रावास (29,120), उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी कार्यालय (57,600), गोपिचंद विजय कुमार जैन कन्या इंटर कॉलेज, दीना नाथ इंटर कॉलेज, जिला पंचायत अध्यक्ष डाक बंगला, रविदास मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर, जनता भद्रा, लेखपाल कार्यालय, रामलीला कमेटी, स्वामी दयाल, राजेंद्र सिंह और लीलावती सहित कई नाम शामिल हैं। नगर पंचायत की इस कार्रवाई को लेकर पूरे नगर में चर्चओं का दौर शुरू हो गया है। आम नागरिक सवाल उठा रहे हैं कि जब सरकारी कार्यालय स्वयं करें का भुगतान नहीं कर रहे हैं तो आम जनता पर सख्ती क्यों की जा रही है। इस मामले में नगर पंचायत की अर्थ एवं कर निर्धारण अधिकारी रेणुका यादव ने बताया कि यह कार्रवाई जिलाधिकारी के निर्देश पर की गई है। सभी बकायेदारोंको नोटिस जारी किए जा चुके हैं। यदि निर्धारित समय सीमा में गृहकर और जलकर जमा नहीं किया गया, तो नियुक्त आरोप आरसी काटकर वसूली की कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत के इस कदम को जहां एक ओर सख्ती के रूप में देखा जा रहा है वहीं दूसरी ओर इसे कर वसूली में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम भी माना जा रहा है।

नाबालिग से दुर्घर्म के अभियुक्तको 10 वर्ष का कारावास

न्यूज़ वाणी ब्यूरो
नानपारा, बहराइच। थाना कोतवाली नानपारा के एक गांव निवासी वादिनी की पीड़िता लक्ष्मी उम्र लगभग 13 वर्ष, घटना 16 अक्टूबर 2016 में बांछित अभियुक्त उचित राम उर्फ पंजाबी पुत्र साधुराम पाल द्वारा अन्य साथियों के साथ पीड़िता को बहला फुसला कर भाग ले जाने व दुर्घर्म के आरोपी अभियुक्त उचित राम के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित हुआ। दुर्घर्म से संबंधित धाराओं में दोष सिद्ध होने के पश्चात अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास तथा 35000 रुपया अर्थदंड से न्यायालय ने दंडित किया है।

गांधी हटाओ-गरीब मिटाओ नीति के खिलाफ सांसद का उपवास सत्याग्रह

- गांधी, सविधान व गरीब तीनों पर हमला कर रही सरकार : राकेश राठौर

न्यूज़ वाणी ब्यूरो
सीतापुर। सांसद राकेश राठौर ने अंबेडकर पार्क में मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने और



संसदीय समिति की सिफारिशों को दबाने के खिलाफ आज उपवास सत्याग्रह शुरू किया। सांसद का उपवास सत्याग्रह सुप्रसिद्ध लेखक अरुण अवध ने जूस पिलाकर खत्म कराया। सांसद राकेश राठौर ने कहा कि भाजपा नीति केंद्र सरकार मनरेगा को धीरे धीरे खत्म करने

की नीति पर काम कर रही है। गांधी का नाम हटाना उसी साजिश का हिस्सा है ताकि रोजगार की संवैधानिक गारंटी को खत्म किया

जा सके। उन्होंने कहा कि डां अंबेडकर नेहरु के बाद अब गांधी पर पर भाजपा हमला कर रही है क्योंकि यही तीन महापुरुष भाजपा के तानाशाही हिन्दू राष्ट्र बनाने की साजिश में बाधा हैं। कांग्रेस किसी भी सूरत में भाजपा की साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। इस

एग्नो क्लाइमेटिक जोन स्तरीय मेला व प्रदर्शनी का जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया शुभारंभ

न्यूज़ वाणी ब्यूरो

मऊ। कलेक्ट्रेट प्रांगण में तीन दिवसीय एग्नो क्लाइमेटिक जोन स्तरीय मेला व प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस दौरान उन्होंने इस प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा .षि से संबंधित लगाए गए इंस्टालो का अवलोकन भी किया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि इस तीन दिवसीय प्रदर्शनी के आयोजन में जनपद के समस्त किसान भाई उपस्थित होकर इसका लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ .षि विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा वहां पर उपस्थित सभी किसान भाइयों को प्रदर्शनी में आने पर धन्यवाद भी दिया। डा. हर्षवर्द्धन ने .षि उपयोगी शुष्म जीवों पर विस्तृत चर्चा किया। बताये कि सुक्ष्म जीवों के उपयोग से फसल उत्पादन में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। डा. वी०क० सिंह द्वारा गेहूँ के प्रक्षेती किस्मों पर चर्चा किया एवं बुवाई जीरो टिल सीइड्डिल से करने की सलाह दी। प्रगतिशील .षक जयप्रकाश सिंह एवं राकेश सिंह द्वारा विद्युत आपूर्ति दिन में देने की माँग की गयी। इस दौरान रामबाबू, परियोजना निदेशक, सोम प्रकाश गुप्ता, जिला .षि अधिकारी, डा. हर्षवर्द्धन एन.वी.आईएम, कुशमीर, डा. बीके सिंह, वैज्ञानिक कवीकें पिलखी, जयप्रकाश सिंह, राकेश सिंह, वीपी सिंह चन्देल प्रगतिशील किसान, रामदयाल राय, अध्यक्ष किसान मोर्चा, राजेश श्रीवास्तव, उदघोषक आदि गणमान्य उपस्थित रहे।

दुर्गावती में कागजों में चल रहा आंगनबाड़ी केंद्रों का खेल

- आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को मानक के अनुसार नहीं मिलती सुविधाएं

न्यूज़ वाणी ब्यूरो
दुर्गावती, कैमूर। जिले के स्थानीय प्रखंड दुर्गावती मे आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को मानक के अनुसार पोषण आहार और सुविधाएं न मिलने की शिकायतें आम हैं, जिनमें मेन्पू के अनुसार खाना न मिलना, अंडे और दूध जैसी चीजें न होने, केंद्र का दर से खुलना या बंद रहना, और पढ़ाई–लिखाई का अभाव प्रमुख हैं, जिससे अभिभावक नाराज हैं और कई बार विरोध भी करते है जबकि अधिकारी जांच और कार्रवाई का आश्वासन देते हैं। मौनब्रत रह जाते है। ग्रामीणों मे इस विषय पर काफी चर्चाएं बना हुआ है। लेकिन जिलें के दुर्गावती प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत करीब 80 आंगनबाड़ी केंद्र किराए

के भवन में संचालित दिखाए जा रहे हैं। जिनका नियमित रूप से सरकार से किराए भी लिए जाते हैं लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उल्टा नजर दिखाई देता है। चर्चाएं है कि कई आंगनबाड़ी केंद्र सेविकाओं या उनके नजदीकी परिवार के निजी मकान में ही संचालित हो रहें हैं। फिर भी उनको कागजों में किराए का भवन दर्शकर सरकारी धनराशि की उगाही की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है। कि इस पूरे खेल में बाल विकास परियोजना विभाग के सुपरवाइजरों की मिलीभगत साफ तौर पर झलकती नजर दिखाई दे रही है। शिकायतें विभाग तक पहुंचती जरूर हैं,लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल पत्राचार कर मामलें को

गांधी प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस का चेतावनी प्रदर्शन

न्यूज़ वाणी ब्यूरो
बहराइच। मनरेगा से पूज्य बापू महात्मा गांधी जी का नाम हटाए जाने की विरोध में आज कांग्रेस ने शहर के वेयरहाउस परिसर में स्थापित पूज्य बापू महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष चेतावनी प्रदर्शन कर शासन प्रशासन से मनरेगा योजना से महात्मा गांधी जी का नाम ना हटाए जाने की पुरजोर तरीके से मांग की। तथा चेतावनी दी कि यदि मनरेगा से महात्मा गांधी जी का नाम हटया जाता है तो देश और समाज में व्यापक आंदोलन छिड़ जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी भाजपा शासन और प्रशासन की होगी। इस अवसर पर कांग्रेस नेता विनय सिंह ने कहा कि यदि आज महात्मा

गांधी जी जिंदा होते तो पुन: सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन व करो मरो आंदोलन की शुरुआत हो जाती। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना बाधित होने की दशा में देश समाज के गरीब मजदूर तथा कमजोर वर्गों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा ,उन्होंने कहा कि जिस तरह शोषित वंचित पीड़ित जनों के हित में शहीद भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने वंदे मातरम, का उद्घोष किया था इस तरह हम कांग्रेस जनों को जनहित में जारी मनरेगा योजना से छेड़छाड़ करने वाले को सबक सिखाना होगा। इस अवसर पर दांडी यात्री इंद्र कुमार यादव ने कहा की गांधी तेरी सोच पे

बेहतर पुलिसिंग व महिला सुरक्षा पर एसपी का जताया आभार

न्यूज़ वाणी ब्यूरो
बहराइच। बे हतर कानून–व्यवस्था महिला सुरक्षा और जनहित में की जा रही प्रभावी पुलिसिंग के लिए सद्भावना एसोसिएशन की ओर से पुलिस अधीक्षक रामनयन सिंह को सम्मान पत्र सौंपकर आभार व्यक्त किया गया। तहसील मिर्हीपुरवा क्षेत्र की अनुसूचित जाति की महिलाएं

पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचीं और एसपी की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान पुलिस व्यवस्था में वे स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से लगाए जा रहे चौपालों और नियमित संवाद से पुलिस व समाज के बीच विश्वास बढ़ा है। बेहतर गश्त त्वरित कार्रवाई और

अवसर पर आईपीएफ के राज्य सचिव डां बृजबिहारी ने कहा की लोकसभा की संसदीय समिति ने मनरेगा मे 400 रूपए प्रतिदिन मजदूरी और 150 दिन के काम की सिफारिश की थी। कई राज्य सरकारे अपने यहां लगभग 400 रूपए मनरेगा मजदूरी को मजदूरी दे रही है लेकिन केंद्र सरकार ने संसदीय समिति के सुझावो को भी फाइलो मे दफना दिया है। इस अवसर पर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष शिवप्रकाश सिंह ने कहा अगर मनरेगा का मूल चरित्र बरकरार न रखा गया तो जन आंदोलन तेज किया जायेगा। उपवास सत्याग्रह के पहले सांसद राकेश राठौर के नेतृत्व मे सैकड़ो की संख्या मे लोग गांधी पार्क पहुंच कर गांधी प्रतिमा पर मात्पार्षण किया फिर अंबेडकर पार्क पहुंच कर सांसद राकेश राठौर उपवास सत्याग्रह पर बैठ गये। सांसद

राकेश राठौर के उपवास सत्याग्रह के समर्थन मे मजदूर किसान मंच के सैकड़ो मजदूर सुनीला रावत और राधेश्याम कनौजिया के नेतृत्व मे अंबेडकर पार्क पहुंच कर समर्थन मे आवाज बुलंद की उपवास सत्याग्रह मे कांग्रेस की उपाध्यक्ष सुनीता चौधरी ने सांसद राकेश राठौर के समर्थन मे पूरे जिले की सभी 09 विधान सभा क्षेत्रो मे उपवास सत्याग्रह शुरू करने और जिला स्तर पर एक मनरेगा सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा जिसे सर्वसम्मत से पास किया गया। अंबेडकर पार्क मे उपवास सत्याग्रह के दौरान राष्ट्रपति को सम्बोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया कार्यक्रम मे राजेश पाल, जिला कांग्रेस प्रवक्ता एहतिशाम बेग, जिला महामंत्री हसीना खातून, जिला उपाध्यक्ष अनुपमा द्विवेदी शामिल रहे।

क्रिसमस कार्यक्रमों को लेकर विहिप व बजरंग दल ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

न्यूज़ वाणी ब्यूरो
बहराइच। आगामी क्रिसमस पर्व को लेकर तहसील क्षेत्र में आयोजित होने वाले कार्यक्रमोंपर रोक लगाने की मांग को लेकर सेमवार को विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के पदाधिकारियों ने उपजिलाधिकारी मिर्हीपुरवा को ज्ञापन सेंमा। यह ज्ञापन संगठन के विभाग उपाध्यक्ष संदीप सिंह के नेतृत्व मेंसौंपा गया, जिसमें तीन सूत्रीय मांगें रखी गईं। ज्ञापन में कहा गया है कि मिर्हीपुरवा तहसील क्षेत्र भारतनेपाल सीमा से सटा होने तथा दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण लंबे समय से संचेदनशील माना जाता रहा है। संगठन का आरोप है कि बीते कुछ वर्षोंसे क्षेत्र मेंधर्मंतरण से जुड़ी गतिविधियोंकी सूचनाएं समय–समय पर मिलती रही हैं जबकि यहां की आबादी मुख्य रूप से हिंदू एवं थारु आदिवासी समाज की है। विहिप बजरंग दल की ओर से यह भी उल्लेख किया गया कि प्रत्येक वर्ष क्रिसमस के अवसर पर खड़िया, मंझाव, हरखापुर, सलारपुर, बेझिया, माधवपुर, घूमनाभारू, सर्रंकला, राणा फार्म सहित कई गांवोंमेंविभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें हिंदू परिवारों को आमंत्रित कर प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। संगठन की प्रमुख मांगोंमेंसरकारी एवं निजी विद्यालयोंमेंईसाई धार्मिक कार्यक्रमोंके आयोजन पर रोक लगाने की बात कही गई है। साथ ही यह भी मांग की गई कि विद्यालयोंमेंपढ़ने वाले हिंदू परिवारोंके बच्चोंको क्रिसमस के अवसर पर आयोजित किसी भी ईसाई धार्मिक नाटक या कार्यक्रम मेंप्रतिभाग करने से रोका जाए। इसके अलावा क्रिसमस के दिन क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखते हुए अनधिकृत रूप से आयोजित होने वाले कार्यक्रमोंपर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। विभाग उपाध्यक्ष संदीप सिंह ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद मिर्हीपुरवा क्षेत्र मेंआयोजित होने वाले ईसाई धार्मिक कार्यक्रमोंका विरोध करता रहा है और भविष्य मेंभी ऐसी गतिविधियोंपर नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि क्रिसमस केदिन संगठन के कार्यकर्ताक्षेत्र मेंप्रमणशील रहेंगेऔर यदि किसी प्रकार की अंधे्र गतिविधि पाई जाती है तो उसके लिए आयोजनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस दौरान प्रखंड सहसंयोजक .ष्णा पांडे ,खंड अ्यक्ष हृदयेश, प्रखंड मंत्री संजयकुमार, रंशेन मौर्य, श्याम सिंह, चंद्रिका प्रसाद अरविंद कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

कुएं में मिला नेपाली नागरिक का शव

न्यूज़ वाणी ब्यूरो
रूपईडीहा, बहराइच। रूपईडीहा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम निधि नगर पोखरा में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब गांव के एक पुराने कुएं में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। मृतक की पहचान संजय पुत्र राजकुमार गुप्ता के रूप में हुई है, जो नेपाल का नागरिक बताया जा रहा है। वह बीते कई वर्षों से क्षेत्र के गोकुलपुर गांव में रह रहा था। स्थानीय लोगों द्वारा दी गई सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएँ से बाहर निकलवाया और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। प्रारंभिक जांच में शव पर किसी प्रकार की कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार संजय नशे का आदी था। बताया जा रहा है कि घटना से एक दिन पूर्व गांव में छठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें संजय भी शामिल हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि नशे की हालत में संतुलन बिगड़ने से वह कुएँ में गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं पर गंभीरता से पड़ताल की जा रही है।

ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठक सम्पन्न

न्यूज़ वाणी ब्यूरो
बहराइच। देहात इंडिया संस्था के तत्वावधान एसेक्स टू जस्टिस परियोजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत खलीलपुर बरिया, ब्लॉक चितौरा, जनपद बहराइच में ग्राम स्तरीय बाल संस्क्षण समिति की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ग्रामस्तरीय हितधारकों पंचायत प्रतिनिधियों शिक्षकों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं समुदाय के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी की। बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तर पर बच्चोंसे जुड़ी समस्याओंकी पहचान कर उनका समाधान सुनिश्चित करना था। बैठक मेंबच्चोंके अधिकारों शिक्षा, सुखा, और स्वास्थ से संबंधित विभिन्न मुद्दोंपर गहन चर्चा की गई। साथ ही, सरकारी योजनाओंकी जानकारी देकर समुदाय को उनके लाभ से अवगत कराया गया। बैठक में उपस्थित देहात इंडिया से अमरेश कुमार (प्रोग्राम एसोसिएट) ने बच्चों के अधिकारों उनकी सुखा, और सामाजिक कल्याण योजनाओंपर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बाल संस्क्षण समिति की भूमिका को रेखांकित करते हुए सभी सदस्यों से सक्रिय रूप से बच्चों के हित में कार्य करने की अपील की। रचना मिश्रा (टीम सहयोगी देहात इंडिया) जी द्वारा निशुक्ल हेल्प लाइन बच्चों से संबंधित 1098 स्वास्थ्य सेवा से संबंधित 108 महिला सुखा से संबंधित 1090 एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के बारे मेंमहत्वपूर्ण जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक किया। यह बैठक बाल अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रही, जिसमें समुदाय को जागरूक कर बच्चों के लिए एक सुरक्षित और सशक्त वातावरण निर्मित करने का संकल्प लिया गया। बैठक मेंग्राम प्रधान रंजीत दास, दर्शिता श्रीवास्तव पंचायत सहायक, ज्ञानवीर, रंजीता देवी, बेबीरोमी आंगनबाड़ी, मीना देवी, चंद्रकला आशा सुनील कुमार कनौजिया सहायक अध्यापक एवं देहात इंडिया टीम से अमरेश कुमार, रचना मिश्रा आदि लोगोंसहित बाल संस्क्षण के विभिन्न पहलुओंपर अपने विचार साझा किए।

डीएम ने ली एफपीओ की जिला स्तरीय अनुसरण समिति की बैठक

न्यूज़ वाणी ब्यूरो
फिरोजाबाद। जिलाधिकारी रमेश खंन ने कहा कि जनपद के समस्त एफपीओ किसानों की आय बढ़ाने के लिए बेहतर रणनीति तैयार करेतथा बेहतर इनपुट एवं उत्पादन प्रबंधन के साथ ि उत्पादों की प्रोसेसिंग के माध्यम से किसानों की आई बढ़ाने में आगे आए। उन्होंने एलडीएम को निर्देशित किया एफपीओ को आसान ऋण उपलब्ध कराया जाय। उन्होंने बताया कि जनपद

में सात नए एफपीओ का गठन किया जाना है। भारत सरकार द्वारा चयनित संस्था फेडर ट्रेड बास्केट इंडिया लिमिटेड द्वारा फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, नारखी, एका, अराव, जसराना, मदनपुर मेंये एफपीओ गठित किए जाएंगे। जिलाधिकारी द्वारा संस्था के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि अब तक किए गए कार्योंका ब्यौरा तैयार कर एक सप्ताह मेंप्रस्तुत करें। पूरी पारदर्शिता के साथ एफपीओ का गठन किया जाए। प ि निदेशक रतेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि समस्त एफपीओ पूरी शक्ति पेंटेल पर अपना डाटा अपडेट करा देंजिससे उनकी प्रेडिा हो सके। जिला उद्यान अधिकारी अनिता सिंह ने कूपर प्रेसेसिंग की योजनाओंकी जानकारी दी। जिला ि अधिकारी सुमित चौहान ने बताया कि एफ पी ओ किसानों को संतुलित उर्वरक प्रयोग के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर लीड बैंक मैनेजर, प्रमारी मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सहित समस्त एफ पी ओ निदेशक उपस्थित रहे।

